सांध्य दैनिक

4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 10 ● अंकः 202 ● पृष्ठः 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 29 अगस्त, 2024

मूल्य ₹ 3/-

अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त मत बर्बाद करें, क्योंकि वह वक्त ही है जिससे जिंदगी बनी होती है।

-ब्रूस ली

शव पर राजनीति कर लाभ लेना चाहती... 7 | बिहार में अभी से सजी सियासी... 3 | भाजपा राज 'भ्रष्टाचार-अपराध' की... 2

महिला सुरक्षा पर खरगे ने दिखाया सरकार को आईना

महिलाओं को संरक्षण नहीं भयमुक्त वातावरण चाहिए

- बोले- हमें बेटी बचाओ नहीं बेटी को बराबरी का हक सुनिश्चित करना चाहिए
- कहा- देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध हो रहे दर्ज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से देश के अंदर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर अभी भी लोगों में आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के बदलापुर में और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी महिला के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आई हैं। यही नहीं देश में जब तब महिलाओं के साथ अपराध या अपमान की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। इसको लेकर सियासत और हो हल्ला भी खूब होता है लेकिन इन पर अंकुश अभी तक नहीं लग पाया है। आए दिन महिलाओं के साथ हो रहीं इन घटनाओं को लेकर अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी दुख जताया है। साथ ही देश की मोदी सरकार से भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय व अपराध को लेकर सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर दुख जताया साथ ही केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खरगे ने लिखा कि हमारी महिलाओं के साथ हुआ कोई भी अन्याय असहनीय है, पीड़ादायक है और घोर निंदनीय है। खरगे ने कहा कि हमें 'बेटी बचाओ' नहीं 'बेटी को बराबरी का हक सुनिश्चित करो' चाहिए। महिलाओं को संरक्षण नहीं, भयमुक्त वातावरण चाहिए।

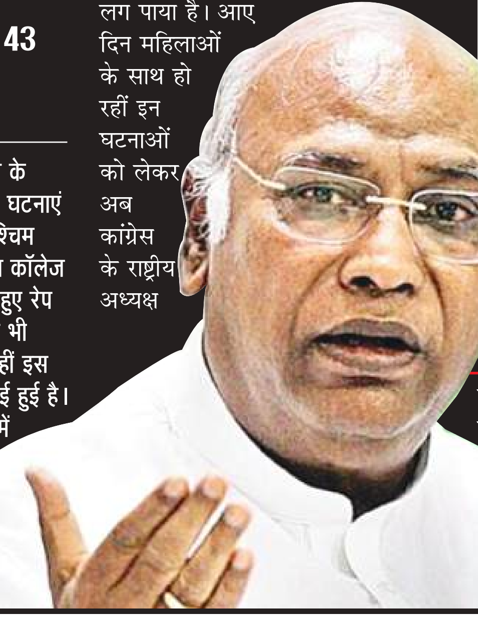

अब वक्त आ गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे लिखा कि संविधान ने महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा है। इन अपराधों को रोकना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम सबको एकजुट होकर, समाज के हर तबके को साथ लेकर इसके उपाय तलाशने होंगे। खरगे ने कहा कि चाहें जेंडर संवेदीकरण की बात हो या जेंडर बजटिंग हो, वूमेन पॉवर लाइन हो या हमारे शहरों में स्ट्रीट लाइट्स और महिला शौचालय जैसी जैसी मूलभूत सुविधा, या फिर हमारे पुलिस रिफॉर्म हो या न्यायिक रिफॉर्म अब वक्त आ गया है कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित हो सके।

पीएम की पार्टी ने कई बार किया पीड़िता का चरित्र हनन

मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे लिखा कि देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं। हर दिन 22 अपराध ऐसे हैं, जो हमारे देश के सबसे कमजोर दलित-आदिवासी वर्ग की महिलाओं व बच्चों के खिलाफ दर्ज होते हैं। अनगिनत ऐसे अपराध हैं जो दर्ज ही नहीं होते - डर से, भय से, सामाजिक कारणों के चलते। पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के भाषणों में कई बार महिला सुरक्षा पर बात कर चुके हैं, पर उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कुछ ठोस नहीं किया जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ रोकथाम हो। उल्टा, उनकी पार्टी ने कई बार पीड़िता का चरित्र हनन भी किया है, जो शर्मनाक है।

खरगे ने पूछे तीखे सवाल

कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए पूछा कि हर दीवार पर 'बेटी बचाओ' पेंट करवा देने से क्या सामाजिक बदलाव आएगा या सरकारें व कानून व्यवस्था सक्षम बनेगी? क्या हम निवारक कदम उठा पा रहे हैं? क्या हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कोई सुधार आया है? क्या समाज के शोषित व वंचित अब एक सुरक्षित वातावरण में रह पा रहे हैं? क्या सरकार और प्रशासन ने वारदात को छिपाने का काम नहीं किया है? क्या पुलिस ने पीड़िताओं का अंतिम संस्कार जबरन करना बंद कर दिया है, ताकि सच्चाई बाहर न आ पाएं? हमें ये सोचना है कि जब 2012 में दिल्ली में 'निर्भया' के साथ वारदात हुई तो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू हुई थी, आज क्या उन सिफारिशों को हम पूर्णतः लागू कर पा रहे हैं? क्या 2013 में पारित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का ठीक ढंग से पालन हो रहा है, जिससे कार्यस्थल पर हमारी महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण तैयार हो सके?

बारिश ने खोली गुजरात मॉडल की पोल

- मुख्य शहरों में भरा पानी टूटने लगीं सड़कें
- राज्य की 916 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अहमदाबाद। गुजरात में आसमान से लगातार आफत बरस रही है। जी हां, क्योंकि प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश वहां के लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। इस बारिश के चलते राज्य में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। साथ ही लोगों को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि पूरे के पूरे शहर पानी से भरे हुए हैं। आलम ये है कि कई जगहों पर लोगों के घरों तक में पानी भर रहा है। प्रदेश के वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में मेन सिटी के अंदर भी सड़क पर पानी कमर से ऊपर हो रखा है। सड़कें टूट रही हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग्स बहती दिख रही हैं। कहीं न कहीं बारिश ने भाजपा के गुजरात मॉडल की पोल खोलकर रख दी है। प्रदेश में बारिश की चेतावनी लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और बारिश की वजह से पिछले तीन दिनों में प्रदेश में 28 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से राज्य में 916 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 66 राज्य राजमार्ग वाहन यातायात के लिए बंद हैं। 758 पंचायत वाली सड़कें बंद हो गईं, जबकि अन्य 88 सड़कें बंद हो गई हैं। पोरबंदर जिले में 90 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं।

वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क टूटी

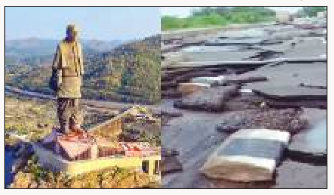

इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सड़क टूट गई। जिसके चलते एक तरफ की सड़क को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मूसलाधार बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से सड़क टूट गई। रोड इस तरह से टूटा है कि उसके बनने में कई महीने लग सकते हैं। बारिश रुकने पर ही रोड बनाने का काम शुरु किया जाएगा। भारी बारिश की वजह से जिस तरह से गुजरात में सड़कें टूट रही हैं और मुख्य शहरों में पानी भर रहा है, वो गुजरात मॉडल की पोल खोलता है और गुजरात में विकास के दावों पर सवाल उठाता है।

भाजपा राज 'भ्रष्टाचार-अपराध' की जुगलबंदी बनकर रह गया : अखिलेश

बोले- दिनदहाड़े हुई लूट दर्शाती है कि प्रदेश में किसका अमृतकाल चल रहा है

» सुल्तानपुर में सर्राफ की दुकान पर हुई लूट पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है। एक ओर सरकार की ओर से भले प्रदेश में कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने की बात कही जा रही हो, लेकिन आए दिन प्रदेश में हो रही घटनाएं सरकार के ऐसे दावों की पोल खोलती हैं।

वहीं विपक्ष को ये घटनाएं बैठे-बिठाए एक मुद्दा भी दे देती हैं। इसी क्रम में सुल्तानपुर में कोतवाली से पांच सौ मीटर की दूरी पर चौक क्षेत्र मेजरगंज में असलहाधारी बदमाशों ने बुधवार को दिनदहाड़े एक आभूषण की दुकान से करोड़ों रुपये के जेवरात और नकदी लूट ली। इस लूट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस घटना के वीडियो को शेयर करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

भाजपा राज में शासन-प्रशासन सिर्फ नाम का ही रहा

लूट की घटना का वीडियो शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुल्तानपुर के भीड़-भाड़ वाले इलाके चौक घंटाघर में दिनदहाड़े सुनार की दुकान पर हथियार के बल पर डकैती में 5 करोड़ रूपये की बेखौफ लूट दर्शाती है कि भाजपा राज में किसका अमृतकाल चल रहा है। भाजपा आपसी लड़ाई में इतनी उलझ गयी है कि शासन-प्रशासन बस नेम प्लेट पर लिखे पदनाम तक ही सीमित हो गया है। सपा मुखिया ने लिखा कि भाजपा राज 'भ्रष्टाचार-अपराध' की जुगलबंदी बनकर रह गया है।

प्रदेश में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं : शिवपाल यादव

समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुल्तानपुर से

मिले लूट की सीसीटीवी की तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा है कि प्रदेश में अपराधी बिलकुल बेखौफ हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावे का का अर्थ क्या है। कहीं सरकार ने अपराधियों के लिए ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीति तो लागू नहीं कर दी है।

पांच लोगों ने मिलकर की दो करोड़ की लूट

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सर्राफा व्यापारी भरत जी सोनी के आवास में ही दुकान है और दोपहर करीब 12 बजे दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच व्यक्ति दुकान में घुसे। उन्होंने बताया कि दुकान में घुसे पांच बदमाशों में से तीन ने हेलमेट लगा रखा था जबकि एक व्यक्ति ने गमछे से मुंह ढक रखा था और एक ने सिर में गमछा लपेट रखा था। अधिकारी ने बताया कि हेलमेट लगाए दो बदमाशों ने असलहे के बल पर दुकानदार और उसके बेटे को रोके रखा और तीन बदमाशों ने जेवरात और नकदी को एक बैग में भरा लिया। उन्होंने बताया कि 10 मिनट में दुकान खाली कर बदमाश मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना के खुलासे के लिए अपराध शाखा समेत छह टीमें लगाईं गई हैं। लगभग दो करोड़ रुपये के जेवरात लूटे जाने की तहरीर कोतवाली नगर में दी गई है।

अलग राजनीति कर रहे हैं राहुल : स्मृति

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। अक्सर राहुल गांधी पर हमलावर रहने वाली भाजपा की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल को लेकर बयान दिया है। लेकिन इस बार उनका अंदाज

कुछ अलग रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर स्मृति ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी की राजनीति बदल गई है। वो एक अलग राजनीति कर रहे हैं। वो चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लेकिन वो अलग है।

स्मृति ईरानी ने एक कार्यक्रम में तमाम मुद्दों को लेकर बात की। इस दौरान जब उनसे राहुल गांधी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता हासिल की है।

राहुल गांधी जानते हैं वो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं

बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो संसद में टीशर्ट पहन रहे हैं, वो जानते हैं कि उस सफेद टीशर्ट से वो युवा पीढ़ी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। हम इस गलतफहमी में न रहे कि वो कोई भी कदम है। वो कदम चाहे आपके अच्छा लगे या बुरा लगे। वो आपको बचकाना लगे। लेकिन, वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं।

'सर्पदंश से मौत पर परिवारों को मुआवजा देने पर करेंगे विचार'

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य सरकार सर्पदंश से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार राहत नियमावली में आवश्यक संशोधन भी करेगी।

कांग्रेस के केवल सिंह पठानिया के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में हस्तक्षेप करते हुए सुक्खू ने कहा कि नदियों और खड्डों के आसपास के क्षेत्रों में बरसात के दौरान सर्पदंश के मामले बढ़ जाते हैं और उन्होंने राजस्व मंत्री से इस मुद्दे पर और जानकारी जुटाने को कहा है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल्य ने कहा कि सर्पदंश

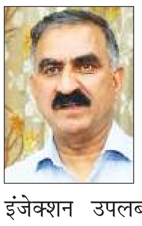

के मरीजों को तुरंत उपचार दिया जाएगा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जहर रोधी इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा एंबुलेंस में भी ये इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। सुक्खू ने राज्य विधानसभा में कहा कि सेवा के दौरान मरने वाले 1,400 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अगले नौ महीनों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सदन में एक सवाल के जवाब में सुक्खू ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के 1,415 मामले सरकार के समक्ष लंबित हैं और उनकी सरकार ने पिछले 20 महीनों में 180 लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी है।

कंगना एक बददिमाग महिला : संजय

बोले- किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना अपमानजनक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हिमाचल स्थित मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत से जुड़े सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना को एक बददिमाग महिला करार दिया। आप सांसद ने कहा कि वो एक बददिमाग महिला है और उसे कतई संसद में नहीं पहुंचाना चाहिए था। किसानों को बलात्कारी और हत्यारा कहना बहुत ही अपमानजनक है और बीजेपी को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए।

वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर संजय सिंह ने कहा जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे क्योंकि ये गांधी, गौतम बुद्ध भगवान कृष्ण का देश है। उन्होंने कहा कि ये देश उन मान्यताओं पर यकीन करता है जहां हम प्रेम और अहिंसा की

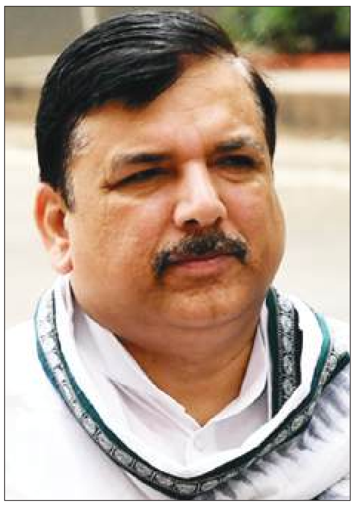

बात करते हैं, नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।

23 साल पुराने मामले में संजय सिंह को हाईकोर्ट से मिली राहत

बता दें 23 वर्ष पूर्व बिजली पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर एक आंदोलन हुआ था। जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित 6 दोषियों को एमपी एमएलए कोर्ट ने तीन तीन माह कारावास की सजा और डेढ़ डेढ़ हजार जुर्माने का आदेश दिया था। इसी को लेकर इन लोगों ने शेषन कोर्ट में अपील की थी। लेकिन वहां अपील खारिज कर दी गई थी और लोवर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। लेकिन यहां सरेंडर करने के बजाय बीते 22 अगस्त को संजय सिंह ने हाइकोर्ट का सहारा लिया। जहां से उन्हें जमानत मिल गई। संजय सिंह मुचलका भरने सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे थे। जहां 50 - 50 हजार के निजी मुचलके पर ट्रायल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई।

हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं जो सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करते हैं : अजित

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है और समाज सुधारक डॉ. बी.आर. अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले और छत्रपति शाहू महाराज की विचारधारा का पालन करती है। अजित पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी समुदायों को एकजुट करके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की।

एनसीपी प्रमुख ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं, जो शासन करते हुए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करती है। पवार ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी अन्याय को रोकने के लिए काम कर रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी को भी अनुचित तरीके से परेशान

नहीं किया जाए या उनकी जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार की लाड़ली बहन योजना चुनाव के बाद बंद नहीं की जाएगी। पवार ने कहा कि यह योजना अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। अजित ने कहा कि अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की सोच के साथ तालमेल बिठाती है, तो राज्य को अधिक धन मिलता है, जिससे उसका विकास होता है। उन्होंने लोगों से विपक्ष के इस दुष्प्रचार पर कभी विश्वास न करने को कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार संविधान को बदलने की योजना बना रही है।

बिहार में अभी से सजी सियासी चौसर

जातिगत जनगणना व वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मतभेद

- विधानसभा चुनाव-25 पर सबकी नजर
- भाजपा के सहयोगी बढ़ा रहे परेशानी
- जदयू-लोजपा भी मुखर
- राजद नेता तेजस्वी ने अकेले ही संभाला मोर्चा
- वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा के लिए आगे की राह आसान नहीं

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। जातिगत जनगणना व वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई। बीजेपी के ऊपर विरोधी राजद तो इन मुद्दों को लेकर हमलावर है उसके सहयोगियों ने भी अपने बयानों से परेशान कर दिया है। गौरतलब हो कि देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा पिछले दिनों से काफी जोर पकड़ रहा है। विपक्ष एक सुर में सरकार पर दबाव बनाते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है।

इसलिए जातिगत जनगणना पर सरकार और विपक्षी दलों के नेता आमने-सामने भी होते रहते हैं। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी याद ने फिर से जातिगत जनगणना पर बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना की हमारी बहुत पुरानी मांग है। राजग में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी राम बिलास ने जातिगत जनगणना को सही ठहराया है। हालांकि जदयू नेता ललन सिंह ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना की जदयू की मांग को कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने कई बार 'अस्वीकार' कर दिया। जद(यू) के विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन में रहने के दौरान पार्टी के अध्यक्ष रहे सिंह गठबंधन की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहते थे। वहीं वक्फ बोर्ड सशोंधन बिल पर भी नीतिश व चिराग जल्दबाजी के मूड में नहीं हैं।

वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा के लिए आगे की राह आसान नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) भी इस बिल से खुद को दूर करती हुई दिखाई दे रही है। यहीं कारण है कि भाजपा की टेंशन बढ़ सकती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) पहले ही विधेयक पर सवाल पूछ चुकी है, साथ ही आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु की तेलुगु देशम पार्टी भी इस विधेयक पर सवाल उठा चुकी है। अब नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) भी सवाल करती हुई दिखाई दे रही है। माना जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की पार्टी मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए प्रस्तावित कानून में बदलाव चाहती है, जो राज्य की आबादी का 18 प्रतिशत हिस्सा हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। शुरुआती समर्थन को देखते हुए जेडीयू की लाल झंडी महत्वपूर्ण है। पार्टी सांसद राजीव रंजन ने इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में एक बहस के दौरान कानून के पक्ष में बात की थी। रंजन ने संशोधनों को पारदर्शिता के लिए एक बहुत जरूरी उपाय बताया। हालाँकि, तब से, जदयू के गुटों के भीतर असंतोष है, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद ज़मा खान ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। अफवाहें कहती हैं कि खान एकमात्र असहमति की आवाज नहीं हैं, जल संसाधन मंत्री संसदीय विजय कुमार चौधरी ने मुस्लिम समुदाय की आशंकाओं के बारे में बात की है। चौधरी को व्यापक रूप से मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी के रूप में देखा जाता है। रिपोर्टों में कहा गया है कि विधायक गुलाम गौस जैसे अन्य जदयू नेताओं ने भी संदेह व्यक्त किया है। नए कानून की धाराओं पर स्पष्ट रूप से बढ़ती आपत्ति के परिणामस्वरूप जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और खान ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। वहीं, वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति ने बृहस्पतिवार को मैराथन बैठक की जिसमें कई विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्तावित कानून के कई प्रावधानों को लेकर आपत्ति जताई। समिति की इस पहली बैठक के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से एक प्रस्तुति दी गई। सूत्रों ने बताया कि देश भर से विधेयक पर व्यापक राय लेने के मकसद से समिति के प्रयासों के तहत लोगों और संस्थानों से अपने सुझाव साझा करने के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

इंडिया गठबंधन ने कई बार 'अस्वीकार' किया : ललन

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना की जदयू की मांग को कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने कई बार 'अस्वीकार' कर दिया। जद(यू) के विपक्षी खेमे इंडिया गठबंधन में रहने के दौरान पार्टी के अध्यक्ष रहे सिंह गठबंधन की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहते थे। ललन ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी पार्टी का इस मामले को लेकर समर्थन नहीं किया और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। सिंह ने कहा, राहुल गांधी जाति जनगणना के मुद्दे पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं...वह इस मुद्दे पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं...जब बिहार सरकार ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया था और उस समय हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, तब हम उनसे विपक्षी गठबंधन की बैठक में इस पर प्रस्ताव पारित करने के लिए कहते रहे...दो बैठक हुई...लेकिन राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दबाव में हमारे अनुरोध को ठुकरा दिया...आज वह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी उस समय आई जब पत्रकारों ने देश में जाति जनगणना की राहुल गांधी की ताजा मांग पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण कराया था, तब राहुल गांधी ने कभी इसकी प्रशंसा नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। प्रयागराज में शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा, करीब 90 फीसदी आबादी के पास आवश्यक कौशल और प्रतिभा है, लेकिन वे सिस्टम से जुड़े नहीं हैं। इसलिए हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं।

चिराग पासवान मिला रहे विरोधियों के सुर में सुर

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की ओर से कई मुद्दों पर उनके स्टैंड को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। एनडीए में तो वो हैं लेकिन कई मुद्दों पर सरकार से उनका स्टैंड अलग है.।वह केंद्र सरकार के स्टैंड से असहमति जता रहे हैं। अलग रुख अपनाए हुए हैं. विरोधियों के सुर में सुर मिला रहे हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चिराग पासवान का सरकार से उलट रुख रहा। वहीं जातीय गणना पर विपक्ष की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जातीय गणना होनी चाहिए, राहुल गांधी एवं अखिलेश यादव ने जातीय गणना की मांग उठाई थी। विपक्ष के अलावा चिराग ने लेटरल एंट्री के केंद्र सरकार के फैसले का भी विरोध किया। आरक्षण पर भी उनका सहयोगी दलों से अलग स्टैंड दिखा। वहीं दूसरी ओर एससी-एसटी के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्रीमी लेयर को लेकर आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जाति समूहों के लिए निर्धारित कोटा में ही कोटा देकर समूह ये पीछे छूट गई जातियों को मौका देना चाहिए। यानी एससी-एसटी में क्रीमीलेयर तय करना चाहिए। चिराग ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की थी। ऐसे में सवाल है कि चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? चिराग के मन में क्या चल रहा है यह पहेली बन गई है।

पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया : शिवराज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किये गये प्रयासों को नरेन्द्र मोदी सरकार की तारीफ की तथा कांग्रेस नीत विपक्ष पर इस वर्ग के वास्ते महज 'जुबानी जमाखर्च' करने का आरोप लगाया। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मंडल 'धानुक' थे और धानुक एक पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) है जिसे ''मेरे राज्य एवं बिहार में राष्ट्रनिर्माण में योगदान के लिए जाना जाता है। हमारे विरोधी पिछड़े वर्गों के नाम पर केवल दिखावा करते हैं जबकि वर्तमान भाजपा शासन में ही उसे (पिछड़े वर्ग को) उसका हक मिला और इस शासन में एक 'अति पिछड़ा' (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) नरेन्द्र मोदी के हाथों में सत्ता की कमान है। यह मोदी ही हैं जिन्होंने 'नीट' जैसी प्रवेश परीक्षाओं में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। यही वह सरकार है जिसने राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। इसकी तुलना कांग्रेस से कीजिए जो कालेलकर आयोग की सिफारिशों पर सोती रही।

जातिगत जनगणना के लिए सरकार को मजबूर करेंगे : तेजस्वी

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जब जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से यह हमारी मांग रही है. उसी का परिणाम रहा कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने जातिगत गणना कराने का निर्णय भी लिया था। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बनने पर वह निर्णय पलट दिया। नीतीश कुमार जी भी वाजपेयी जी नेतृत्व में उसी कैबिनेट का हिस्सा थे। आरजेडी नेता ने कहा कि लालू प्रसाद सहित प्रमुख समाजवादियों ने संसद में पुरजोर तरीके से अपनी बात रख तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा जातिगत गणना/सामाजिक आर्थिक सर्वे कराने की स्वीकृति देने के बाद ही संसद चलने दी थी। सरकार ने वर्षों बाद होने वाली की देश जनगणना भी नहीं कराई। हमने तो केवल कुछ महीनों के अल्प सेवाकाल में बिहार में जाति आधारित गणना करा और उसी अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया। अगर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना नहीं कराई तो वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपेक्षित वर्गों के लोग भाजपाइयों को क्षेत्र में नहीं घुसने देंगे। एनडीए को समर्थन दे रहे क्षेत्रीय दल बिना रीढ़ के हड्डी के सिद्धांतहीन लोगों के हाथ में है। देख लेना हम आपको जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर करेंगे ही करेंगे।

जिद... सच की

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

सरकारी भ्रष्टाचार पर कब लगेगी लगाम!

"अभी ताजा मामला मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष, प्रथम हिन्दू नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गयी 35 फीट ऊंची प्रतिमा का थरथरा कर गिर जाने का है। यह एक राष्ट्रीय शर्म एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार का दु:खद अध्याय है। इस तरह हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी इस प्रतिमा का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है।"

सरकारी काम करने के तरीके से पूरा देश वाकिफ है। पर जिस तरह से मोदी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है उसके इतर कुछ दिनों से केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्मित किए गए कई विकास परियोजनाओं के गिरने की खबरें आती जा रही वह सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रही हैं। अभी ताजा मामला मराठा पहचान और परम्परा के प्रतीक पुरुष, प्रथम हिन्दू नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में की गयी 35 फीट ऊंची प्रतिमा का थरथरा कर गिर जाने का है। यह एक राष्ट्रीय शर्म एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार का दु:खद अध्याय है। इस तरह हमारे एक महानायक की महान स्मृतियों से जुड़ी इस प्रतिमा का गिरना एवं ध्वस्त होना सरकार में गहरे पैठ चुके भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं रिश्वतखोरी को उजागर करता है।

आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में जिस तीव्रता से व्याप्त है, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है, जो सरकार की साख को धुंधला रही है, यह घटना भारतीय नौसेना की साख को भी बट्टा लगा रही है, यह घटना इसलिए भी गंभीर चिंता की बात है कि इससे हमारे सार्वजनिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की कलई खुल गई है। गौर कीजिए, इस प्रतिमा के निर्माण पर करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत आई थी और इसी 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर इसका अनावरण किया गया था। यहीं नहीं अभी हाल ही दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा के एयरपोर्ट व संसद के नए भवन में बारिश के पानी के टपकने की खबरें भी सरकारी काम करने व्यवस्था का पोल खोल रही हैं। सवाल है कि जब सरकार किसी कंपनी को ऐसे राष्ट्रीय महत्व के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपती हैं, उससे पहले क्या गुणवत्ता की कसौटी पर पूरी निर्माण योजना, डिजाइन, प्रक्रिया, सामग्री, समय-सीमा और संपूर्णता को सुनिश्चित किया जाना जरूरी समझा जाता? देश में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है, विशेषत: राजनीतिक एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने देश के विकास को अवरूद्ध कर रखा है। यही कारण है कि पुल या दूसरे निर्माण-कार्यों के लिए रखे गए बजट का बढ़ा हिस्सा कमीशन-रिश्वतखोरी की भेंट चढ़ जाता है। इसका सीधा असर निर्माण की गुणवत्ता पर पड़ता है। निर्माण घटिया होगा तो फिर उसके धराशायी होने की आशंका भी बनी रहती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने की पारदर्शी नीति नियामक केन्द्र बनाने के साथ उस पर अमल भी जरूरी है। सवाल यहां पर यही हैं कि यह घटनाएं केवल खबरें मानकर भूला दी जाएंगी या नीति नियंता इस पर कुछ ठोस निर्णय लेंगे ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

मोदी की यूक्रेन यात्रा में निहित संदेश

ज्योति मल्होत्रा

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूक्रेन की राजधानी कीव के एक बगीचे में लगी महात्मा गांधी की मूर्ति को श्रद्धा सुमन भेंट करने के अवसर पर कुछ अति उत्साही भारतीयों द्वारा 'हर-हर मोदी' और 'जय श्री राम' के नारे लगाने से माहौल की संजीदगी को कुछ हद तक ठेस पहुंची होगी। कुछ मिनट बाद, रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों के यादगार स्मारक के सामने मोदी और व्लोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई मुलाकात में भावनाएं जिस प्रकार स्पष्टत: उमड़ती दिखी, वह भारत के समक्ष उत्पन्न उस धर्मसंकट का भी द्योतक रही, जो इस युद्ध में मध्य मार्ग चुनने से बना है। पृष्ठभूमि समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं। रूस ने युक्रेन पर आक्रमण किया और इसकी भरपूर निंदा होनी चाहिए - कई भारतीयों के अलावा बहुत से रूसी भी इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन बारीकी से देखने पर, अन्य संदर्भ सामने आ जाते हैं। दो साल पहले, नाटो का विस्तार ठीक अपनी सीमा तक पहुंचते देख असुरक्षा की भावना से भरे रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी।

अब यह लड़ाई ऐतिहासिक रूप से साझेदार और सह-धर्मियों के मध्य हार-जीत को लेकर कम बल्कि विश्व पटल पर रूस की जगह को लेकर रूस-अमेरिका के बीच जारी खींचतान की वजह से ज्यादा है। हर कोई, विशेष रूप से यूक्रेनियन, जानता है कि अगर अमेरिका के साथ-साथ पश्चिमी जगत के बड़े हिस्से ने जेलेंस्की के लोगों को अत्याधुनिक हथियार नहीं दिए होते,तो युद्ध कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और निर्दोष लोगों की मौत लगातार जारी है। बड़ी शक्तियों का राजनीतिक खेल हावी हो चुका है। यूक्रेन का यह युद्ध अब इस उद्देश्य को लेकर है 'कौन बनेगा दुनिया का दादा'? 1991 के अंत में सोवियत संघ के विघटन के बाद, साफ है अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति वाला अपना ओहदा छिन जाने को लेकर तैयार नहीं। रूसी भले ही आज अमेरिकियों जितने मजबूत न हों, लेकिन फिर भी काफी शक्तिशाली हैं, और उनका जोर इस बात पर है कि शीर्ष पर एक से अधिक के लिए गुंजाइश है।

हमेशा की तरह चीन 'देखो और इंतजार करो' वाली अपनी नीति के साथ, खुद को दोनों पक्षों के साथ खड़ा दिखाए रखने को उत्सुक और इच्छुक है- जहां एक और वे अमेरिका के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं वहीं ठीक उसी

वक्त व्लादिमीर पुतिन की घर और बाहर, दोनों जगह, प्रासंगिक बने रहने की चिंता भरी जरूरत का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। मोदी ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक कीव में जब जेलेंस्की से कहा : 'भारत शांति की दिशा में किसी भी प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने' को तैयार है, इससे कुछ पल पहले, दोनों ने एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाया था - कुछ हद तक उस लंबी गलबही की तरह जो मोदी और पुतिन ने छह सप्ताह पहले मॉस्को के बाहरी हिस्से में स्थित पुतिन के घर में डाली थी और जिसको लेकर जेलेंस्की ने खुले तौर पर माना था कि इसने उन्हें परेशान कर डाला था। कुछ क्षण बाद, मोदी ने अपना बायां हाथ जेलेंस्की के बाएं कंधे पर रखा, जैसा कि बड़े भाई अक्सर अनुज के साथ करते हैं, और कुछ देर वहीं रखे रखा, इस बीच फोटोग्राफरों ने कई तस्वीरें लीं। ऐसा लगता है कि मोदी वास्तव में द्रवित हुए - यह अच्छी बात है कि वे हुए। भारत आमतौर पर कमजोर के साथ खड़ा होता है - पूर्व पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी का सहयोग इसका एक बढ़िया उदाहरण है। लेकिन यहां तो कुछ और ही होता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है मानो मोदी को एक तरह से राजी किया गया हो कि वे यूक्रेनियों के साथ खड़े दिखाई दें - और इस तरह, परोक्ष रूप से अमेरिका के साथ। अमेरिकियों ने मोदी की मॉस्को यात्रा पर अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तथ्य यह है कि पिछले दो वर्षों में, भारत द्वारा रूस से रियायती दर पर भारी मात्रा में तेल खरीदने से व्यापार के आंकड़े में भारी उछाल बनने के बावजूद, भारत-अमेरिका के बीच लेन-देन अभी भी भारत-रूस व्यापार से दोगुना है।

पश्चिम में जो लोग यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से इनकार करने पर भारत की आलोचना करते हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है - स्वयं पर पक्षपाती होने का आरोप लगने के जोखिम पर, उदाहरणार्थ, उनसे पूछा जाए : 'आपने इस्राइल द्वारा गाजा के अस्पतालों, स्कूलों और संयुक्त राष्ट्र परिसर पर की जाने वाली बमबारी रोकने के लिए क्या किया'? या फिर, मुख्य सहयोगी पश्चिमी मुल्क - जिनमें अधिकांश पांच सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं - क्या इनमें किसी एक ने उस वक्त असहमति की एक छोटी अंगुली तक उठाई, जब 2003 में सद्दाम हुसैन द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों का उपयोग करने की आशंका जताते हुए स्पष्ट रूप से झूठी अफवाह फैलाकर, अमेरिका ने इराक पर बमबारी करने का फैसला किया था।

तंत्र की अदूरदर्शी नीतियों से बाधित शोधकार्य

दिनेश सी. शर्मा

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली) (आईआईटी) और कुछ अन्य शीर्ष रैंकिंग प्राप्त अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों को पिछले पांच वर्षों में मिली अनुसंधान राशि पर जीएसटी कर चुकाने का नोटिस मिला है। बताया गया है कि ब्याज और जुर्माने सहित अकेले आईआईटीडी की रकम 120 करोड़ रुपये बनती है। हालांकि, अकादमिक एवं वैज्ञानिक समुदाय ने इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से गुरेज किया है, लेकिन उद्यमी और निवेशक टीवी मोहनदास पई ने इसको 'कर आतंकवाद का सबसे बुरा रूप' करार दिया है। ठीक एक महीने पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लैब केमिकल्स पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से बढ़ाकर 150 फीसदी कर दिया था। उच्च शुद्धता वाले एंजाइम, अभिकर्मक (रीजेंट्स) और रसायन अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें आमतौर पर आयात करना पड़ता है। इस विचित्र कदम ने वैज्ञानिक समुदाय को सकते में डाल दिया क्योंकि इससे वर्तमान और भविष्य की परियोजनाओं की लागत रातो-रात बढ़ जाती है।

हालांकि, मीडिया और सोशल मीडिया पर वैज्ञानिकों की नाराजगी की प्रतिक्रिया में यह भारी बढ़ोतरी वापस ले ली गई। ये घटनाएं अलग-अलग नहीं हैं, जिन्हें नौकरशाही का अनाड़ीपन ठहराकर रफा-दफा किया जाए बल्कि ऐसी हरकतें जनता के पैसे से चल रहे अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा को कमजोर करने वाली नीति का हिस्सा प्रतीत होती हैं। अनुसंधान फंडिंग पर यह टैक्स नोटिस, तकनीकी उपकरणों पर जीएसटी दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 फीसदी किए जाने के कुछ साल बाद आया है। इससे वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, अन्य मशीनें, सहायक औजार और उपभोग्य सामग्री की खरीद काफी महंगी बन गई। वैज्ञानिक अनुसंधान पर संभावित प्रभावों से चिंतित, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय ने सरकार को एक प्रपत्र भेजा है, जिसमें कहा गया 'हो सकता है कि निजी संगठन टैक्स की दर में हुए परिवर्तन के प्रभावों को धीरे-धीरे पचा भी लें किंतु सार्वजनिक धन से चल रहे संस्थानों के लिए गुंजाइश कम है।' इस पर, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी वृद्धि के वास्तविक प्रभाव को कम करने के वास्ते अतिरिक्त धन आवंटन का वादा करके लीपापोती और पीएसए को शांत करने का प्रयत्न किया। तथापि, सरकार ने स्थितियों में बदलाव के लिए कुछ नहीं किया, जैसा कि हालिया जीएसटी नोटिस और प्रयोगशाला रसायनों पर सीमा शुल्क वृद्धि (अब वापस ले ली गई) जैसे कृत्यों से जाहिर होता है। अनुसंधान एवं नवाचार ऐसे वातावरण में पल्लवित हो सकते हैं जहां सरकार अनुसंधान के वास्ते पर्याप्त धन दे, संयुक्त उपक्रम को प्रोत्साहित और पोषित करे, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के वास्ते उपयुक्त पारिस्थितिकी युक्त तंत्र (विनियमन, कराधान इत्यादि) का निर्माण करे। इन तमाम मोर्चों पर भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। अनुसंधान एवं विकास मद में भारत सरकार की फंडिंग बहुत कम है- सकल घरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत से भी कम। बहुप्रचारित 'अम्ब्रेला रिसर्च फंडिंग एजेंसी' कही जाने वाली 'अनुसंधान राष्ट्रीय खोज फाउंडेशन' (एएनआरएफ), पिछले पांच वर्षों से निर्माणाधीन ही है।

बजट भाषणों में सरकार ने नई एजेंसी के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये 'धन मंजूर करने' का हवाला देते हुए बार-बार दावा किया है कि उसने अनुसंधान एवं विकास के लिए उपलब्ध धन में काफी वृद्धि की है। 'धन मंजूर करना' जुमला भर है क्योंकि इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी फंडिंग का अंश केवल 30 प्रतिशत होगा और शेष 70 फीसदी निजी क्षेत्र को अपने तौर पर जुटाना होगा। यदि ऐसा है, तब भारत सरकार का योगदान 3,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से कम बैठता है जो कि विज्ञान क्षेत्र से संबंधित विभागों के मौजूदा बजट से काफी कम है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 2024-25 के लिए 16,628 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एएनआरएफ की स्थापना अनुसंधान एवं विकास का बोझ निजी क्षेत्र पर स्थानांतरित करने का एक स्पष्ट कदम है, लेकिन ऊपरी तौर यह दिखाई नहीं देता। फंड की कमी के साथ-साथ वैज्ञानिक बिरादरी को लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है, जिसमें शोधकर्ताओं को फंड प्राप्ति, कराधान संबंधी जरूरी प्रक्रिया से निपटना, छात्रवृत्ति और फेलोशिप भत्ते के वितरण में देरी और 'मेक इन इंडिया' नियमावली के अनुसार उपकरणों की खरीद जैसी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने में जूझना पड़ता है।

इस बारे में आईआईटी-कानपुर के एक वैज्ञानिक ने एक्स नामक सोशल मीडिया पर कमेंट किया, 'यदि आपका सारा समय अन्य कार्यों में खपने वाला है तब आप अनुसंधान पर ध्यान कैसे केंद्रित कर पाएंगे?' फिर अनुसंधान को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं, मसलन, ऐसे वक्त में जब महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान मिलकर किया जा रहा हो, वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के वास्ते फंड पर अंकुश लगा दिया गया है। पिछले साल, फाउंडेशन फॉर एडवांसिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एफएएसटी) ने 'ईज ऑफ डूइंग साइंस (ईओडीएस)' -जो कि 2015 में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गढ़ा गया नामकरण है- इसके स्तर को मापने के लिए 10 शीर्ष रैंकिंग संस्थानों के शोधकर्ताओं का सर्वेक्षण किया गया। केवल 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ईओडीएस के किसी भी पैमाने को 'बहुत अच्छा' दर्जा दिया।

द प्रेग्नेंसी बाइबल पर करीना का हाईकोर्ट में जवाब, कहा-

मेरी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने की मंशा नहीं थी

अपनी किताब द प्रेग्नेंसी बाइबल पर अभिनेत्री करीना कपूर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि किताब के टाइटल से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की गई है। न ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी।

फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने अपनी किताब द प्रेग्नेंसी बाइबल पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि किताब के शीर्षक से किसी भावनाओं को आहत नहीं किया गया है। न ही उनकी ऐसी कभी मंशा रही है। दरअसल, किताब के टाइटल को आपत्तिजनक बताते हुए करीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग याचिका में की गई थी। इस पर करीना कपूर खान की तरफ से मंगलवार को जवाब दाखिल किया गया।

हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड में लेने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। दरअसल, जबलपुर के एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में करीना कपूर: द प्रेग्नेंसी बाइबल किताब के टाइटल पर आपत्ति उठाई थी। याचिका में कहा गया था कि बाइबल ईसाई समुदाय की धार्मिक किताब है। इसके कारण इस किताब से समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। याचिका में मांग की गई थी कि करीना कपूर के खिलाफ धारा- 294, 295 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। साथ ही किताब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए करीना कपूर खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन्हें जवाब पेश करने अंतिम बार समय दिया था।

अभिनेता नानी ने कमल हासन की जमकर की तारीफ

नानी साउथ के लोकप्रिय और मशहूर अभिनेता हैं। फैंस उन्हें प्यार से नैचुरल स्टार बुलाते हैं। नानी इन दिनों अपनी फिल्म सारिपोधा सानिवारम को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता को साउथ में पसंद करने वाले फैंस की लंबी कतार है। हालांकि, उन्होंने हाल में ही एक अन्य दिग्गज अभिनेता कमल हासन की प्रशंसा की है। उन्होंने दिग्गज अभिनेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की है। अभिनेता ने कहा कि वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं।

बातचीत के दौरान अभिनेता नानी से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा किन अभिनताओं ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। इसका जवाब देते हुए सारिपोधा सानिवारम अभिनेता ने कमल हासन का नाम लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सिनेमा ने हमें और निर्देशकों को बहुत कुछ दिया है और अगर हमने सिनेमा को कुछ वापस दिया है, तो वह हैं कमल हासन, सर। मुझे लगता है कि वह सिनेमा के लिए ही एक उपहार हैं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई चीजों में महारत हासिल की है। उन्होंने अपना जीवन सिनेमा को दे दिया है। नानी ने कमल हासन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई चीजों में महारत हासिल की है। इसके साथ ही कई तरह के नए-नए प्रयोग भी किए हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस समय में उन्होंने काम किया है, उन्होंने हर चीज सबसे पहले देखी है। उन्होंने सबसे पहले डिजिटल, मेकअप ट्रायल देखा है। अब आगे से जो भी बदलाव होंगे, वो उस पैमाने पर नहीं होंगे। सिनेमा के इस पूरे विकास की प्रक्रिया में कमल सर का योगदान काफी ज्यादा है।

अभिनेता नानी शुरू में बतौर निर्देशक ही फिल्मी करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि किस चीज ने उन्हें निर्देशन को लेकर प्रेरित किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अलग-अलग समय पर उन्हें अलग-अलग निर्देशकों ने प्रेरित किया।

बॉलीवुड | मन की बात

मलयालम इंडस्ट्री के खुलासों पर भड़कीं स्वरा भास्कर

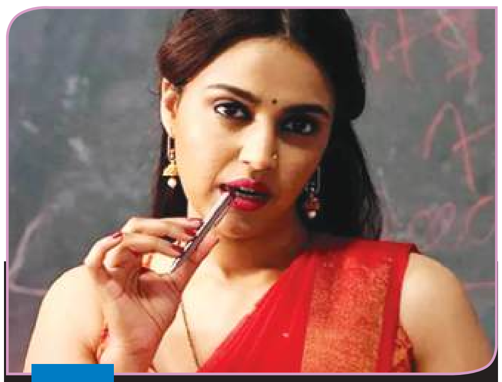

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आई हेमा कमिटी के रिपोर्ट ने हर इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस पर अपना ओपिनियन शेयर किया है। स्वरा के मुताबिक शोबिज वर्ल्ड में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से ही एक पितृसत्तात्मक सोच वाला रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से स्वरा पहली हैं जिन्होंने इस पर बात की है। स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना ओपिनियन शेयर किया और बताया कि वो अपने ये विचार हेमा कमिटी की 233 पेज की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दे रही हैं। स्वरा ने लिखा- क्या भारत में बाकी भाषाओं की इंडस्ट्री भी ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे हैं? जब तक हम उन असहज सच्चाइयों का सामना नहीं करते, जो हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर मौजूद हैं, तब तक सत्ता वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो कमजोर हैं। कमिटी की रिपोर्ट को पढ़ना दिल दहला देने वाला है। और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला इसलिए क्योंकि ये जाना पहचाना है। शायद हर डिटेल और हर बारीकी नहीं, लेकिन महिलाओं ने जो गवाही दी है, उसकी बड़ी तस्वीर सभी को बहुत अच्छे से पता है। शोबिज हमेशा से एक मेल डॉमिनेटिंग इंडस्ट्री रही है, एक पितृसत्तात्मक पावर सेट-अप। ये एक धारणा और सोच है जो बहुत संवेदनशील और जोखिम से भरा हुआ भी है. प्रोडक्शन-शूट के हर दिन, बल्कि प्री और पोस्ट प्रोडक्शन के दिन भी ऐसे दिन होते हैं जब मीटर चलता रहता है और पैसा खर्च होता है. कोई भी रुकावट पसंद नहीं करता. भले ही रुकावट डालने वाले ने एथिकल तरीके से ही सही बात के लिए अपनी आवाज उठाई हो. सबको लगता है बस चलते रहना ज्यादा सुविधाजनक और फाइनेंशियली सही है। हालांकि डिटेल्ड रिपोर्ट 19 अगस्त को जारी की गई थी, लेकिन यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए केरल सरकार ने पैनल का गठन 2017 में किया था। स्वरा ने इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में चुप्पी की परंपरा है और इसकी सराहना भी की जाती है। इतना ही नहीं इसे पूजा तक जाता है, अवॉर्ड दिए जाते हैं।

इस लड़की ने 23 साल से नहीं खाया अन्न, फिर भी पूरी तरह है फिट

अलीगढ़। कहा जाता है कि अगर जन्म से कोई अलौकिक शक्ति के साथ पैदा होता है तो उसे भगवान का अवतार माना जाता है। कुछ ऐसा ही जीवन अलीगढ़ की एक लड़की जी रही है। यहां के सरसौल इलाके में रहने वाली 23 साल की कृष्ण शर्मा ने अपने अनोखे आहार और जीवनशैली से सबको हैरत में डाल दिया है। उनका दावा है कि जन्म से लेकर अब तक उन्होंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, फिर भी वह पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। उनका यह जीवनशैली चिकित्सा और विज्ञान की दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कृष्ण शर्मा की ये असाधारण कहानी न केवल उनके परिवार और पड़ोसियों के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। जहां आम इंसान के लिए अन्न ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत माना जाता है, वहीं कृष्ण की जीवनशैली इस धारणा को चुनौती देती है। कृष्ण शर्मा ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अन्न नहीं खाया। वह केवल फल और जूस पर जीवन यापन करती हैं। उनका कहना है कि अगर वह अन्न से बना कुछ भी खाती हैं, तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक बार उनके पिता ने उन्हें रोटी खिलाने की कोशिश की थी, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कृष्ण का मानना है कि उनके इस असाधारण आहार के पीछे भगवान का आशीर्वाद है। वह भगवान में गहरी आस्था रखती हैं और मां वैष्णो देवी की भक्त हैं। उन्होंने कहा, मुझे कभी अन्न खाने की भूख नहीं लगती और ना ही मैंने कभी अन्न खाया है। मुझे कभी कोई कमजोरी या बीमारी महसूस नहीं होती। कृष्ण शर्मा ने अलीगढ़ के विवेकानंद कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है और अब वह आईएएस की तैयारी कर रही हैं। उनका सपना है कि वह एक दिन कलेक्टर बनें। उनके परिवार में छह बहन-भाई हैं, और वह दूसरे नंबर पर हैं। उनके पिता धीरेन्द्र शर्मा ट्रांसपोर्ट का छोटा सा बिजनेस करते हैं, जबकि उनकी मां रेखा शर्मा एक हाउसवाइफ हैं। इस अनोखी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, अलीगढ़ के डॉक्टर विकास मल्होत्रा ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने आहार में केवल फल, मेवा, जूस और नींबू पानी का इस्तेमाल करता है, तो वह बिना अन्न खाए भी जीवित रह सकता है। हालांकि, कृष्ण की स्थिति दुर्लभ और अनोखी है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अध्ययन का विषय हो सकती है।

अजब-गजब | पूरी दुनिया से सात साल पीछे चल रहा है यह देश

धरती का इकलौता देश, यहां होते हैं साल में 13 महीने

दुनियाभर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जाति और धर्म हैं। लेकिन इन तमाम जगहों पर अगर कोई एक बात सामान्य है, तो वो है साल और महीने। लेकिन दुनिया में कई ऐसी भी संस्कृतियां मौजूद हैं जो साल और तारीख जानने के लिए अलग-अलग तरह के कैलेंडरों का प्रयोग करती हैं। ये सारे कैलेंडर पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे नहीं है। पर वो सभी साल में 12 महीने ही मानते हैं। लेकिन इस धरती पर एक देश ऐसा है, जहां पर साल में 12 नहीं, बल्कि कुल 13 महीने होते हैं। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इतना ही नहीं, 13 महीनों की वजह से ये देश पूरी दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट भी वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो पोस्ट के मुताबिक, इस अफ्रीकी देश का नाम इथियोपिया है। इथियोपिया में 1 साल में कुल 13 महीने होते हैं, जिसमें 13वें महीने में कुल 5 दिन होते हैं, जबकि सप्ताह में कुल 5 दिन। लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है, उस साल इथियोपिया के कैलेंडर में 6 दिन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बता दें कि 2024 का नया साल पूरी दुनिया मना चुकी है, लेकिन

इथियोपिया में इसे 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। बता दें कि दुनिया के ज्यादातर देशों में पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, जो अपने प्राचीन कैलेंडर को मानते हैं। हालांकि, इसके बावजूद सभी कैलेंडरों में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन इथियोपिया में आज भी उसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है जो रोमन चर्च ने 525 एडी में अमेंड किया था। इस वजह से इथियोपिया में नई सदी की शुरुआत 11 सितंबर 2007 से हुई थी।

बता दें कि इथियोपिया इकलौता ऐसा अफ्रीकी देश है, जो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं हुआ। इस पर कभी इटली का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 6 साल बाद ही वो भी चले गए। इतना ही नहीं, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इथियोपिया में ही कॉफी की उत्पत्ति हुई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक इस वीडियो पोस्ट पर अब तक 5 लाख 49 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं, हजारों लोगों ने इसे शेयर और लाइक किया है। कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर अन्य दूसरे देशों के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं, कई यूजर्स मजे लेने के मूड में दिखे। वीडियो पर कमेंट करते हुए जितेंदर भल्ला ने लिखा है कि हमारे भारत में भी 13 महीने का साल होता है, यकीन न हो तो मोबाइल कंपनी के हिसाब से लगाकर देख लो। वहीं, अजीम नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है कि अफ्रीका का यह देश वाकई में अद्भुत है। हमें ऐसी जानकारी नहीं थी।

ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि हैं, लेकिन इथोपियन यानी गीज कैलेंडर के महीनों के नाम भी अलग-अलग हैं। पहला महीना मेस्केरम है, जो नए साल का महीना है। इस महीने की शुरुआत 11 सितंबर से होती है। इसके बाद दूसरा महीना है टिकिम्त । फिर हिदार, तहसास, तिर, याकातित, मग्गाबित , मियाजिया, गिनबोत, सेंसे, हामले, नेहासा और पागुमे हैं।

द प्रेग्नेंसी बाइबल पर करीना का हाईकोर्ट में जवाब, कहा-

मेरी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने की मंशा नहीं थी

अपनी किताब द प्रेग्नेंसी बाइबल पर अभिनेत्री करीना कपूर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि किताब के टाइटल से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की गई है। न ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी।

फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने अपनी किताब द प्रेग्नेंसी बाइबल पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि किताब के शीर्षक से किसी भावनाओं को आहत नहीं किया गया है। न ही उनकी ऐसी कोई मंशा रही है। दरअसल, किताब के टाइटल को आपत्तिजनक बताते हुए करीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग याचिका में की गई थी। इस पर करीना कपूर खान की तरफ से मंगलवार को जवाब दाखिल किया गया।

हाईकोर्ट जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड में लेने का आदेश दिया। साथ ही याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। दरअसल, जबलपुर के एडवोकेट क्रिस्टोफर एंथोनी ने 2022 में करीना कपूर: द प्रेग्नेंसी बाइबल किताब के टाइटल पर आपत्ति उठाई थी। याचिका में कहा गया था कि बाइबल ईसाई समुदाय की धार्मिक किताब है। इसके कारण इस किताब से समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। याचिका में मांग की गई थी कि करीना कपूर के खिलाफ धारा- 294, 295 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। साथ ही किताब की बिक्री पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए करीना कपूर खान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन्हें जवाब पेश करने अंतिम बार समय दिया था।

बॉलीवुड | मन की बात

मलयालम इंडस्ट्री के खुलासों पर भड़कीं स्वरा भास्कर

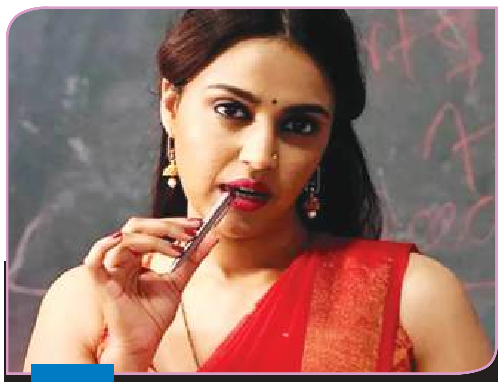

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर आई हेमा कमिटी के रिपोर्ट ने हर इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी इस पर अपना ओपिनियन शेयर किया है। स्वरा के मुताबिक शोबिज वर्ल्ड में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से ही एक पितृसत्तात्मक सोच वाला रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से स्वरा पहली हैं जिन्होंने इस पर बात की है। स्वरा ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना ओपिनियन शेयर किया और बताया कि वो अपने ये विचार हेमा कमिटी की 233 पेज की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दे रही हैं। स्वरा ने लिखा- क्या भारत में बाकी भाषाओं की इंडस्ट्री में ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे हैं? जब तक हम उन असहज सच्चाइयों का सामना नहीं करते, जो हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों ओर मौजूद हैं, तब तक सत्ता वाले लोग इसका गलत इस्तेमाल करते रहेंगे। इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जो कमजोर हैं। कमिटी की रिपोर्ट का पढ़ना दिल दहला देने वाला है। और भी ज्यादा दिल दहला देने वाला इसलिए क्योंकि ये जाना पहचाना है। शायद हर डिटेल और हर बारीकी नहीं, लेकिन महिलाओं ने जो गवाही दी है, उसकी बड़ी तस्वीर सभी को बहुत अच्छे से पता है। शोबिज हमेशा से एक मेल डॉमिनेटिंग इंडस्ट्री रही है, एक पितृसत्तात्मक पावर सेट-अप। ये एक धारणा और सोच है जो बहुत संवेदनशील और जोखिम से भरा हुआ भी है। प्रोडक्शन-शूट के हर दिन, बल्कि प्री और पोस्ट प्रोडक्शन के दिन भी ऐसे दिन होते हैं जब मीटर चलता रहता है और पैसा खर्च होता है। कोई भी रुकावट पसंद नहीं करता। भले ही रुकावट डालने वाले ने एथिकल तरीके से ही सही बात के लिए अपनी आवाज उठाई हो। सबको लगता है बस चलते रहना ज्यादा सुविधाजनक और फाइनेंशियली सही है। हालांकि डिटेल्ड रिपोर्ट 19 अगस्त को जारी की गई थी, लेकिन यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों पर रिसर्च करने के लिए केरल सरकार ने पैनल का गठन 2017 में किया था। स्वरा ने इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में चुप्पी की परंपरा है और इसकी सराहना भी की जाती है। इतना ही नहीं इसे पूजा तक जाता है, अवॉर्ड दिए जाते हैं।

अभिनेता नानी ने कमल हासन की जमकर की तारीफ

नानी साउथ के लोकप्रिय और मशहूर अभिनेता हैं। फैंस उन्हें प्यार से नेचुरल स्टार बुलाते हैं। नानी इन दिनों अपनी फिल्म सारिपोधा सानिवारम को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेता को साउथ में पसंद करने वाले फैंस की लंबी कतार है। हालांकि, उन्होंने हाल में ही एक अन्य दिग्गज अभिनेता कमल हासन की प्रशंसा की है। उन्होंने दिग्गज अभिनेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनकी सराहना की है। अभिनेता ने कहा कि वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक हैं।

बातचीत के दौरान अभिनेता नानी से पूछा गया कि उन्हें सबसे ज्यादा किन अभिनेताओं ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया है। इसका जवाब देते हुए सारिपोधा सानिवारम अभिनेता ने कमल हासन का नाम लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सिनेमा ने हमें और निर्देशकों को बहुत कुछ दिया है और अगर हमने सिनेमा को कुछ वापस दिया है, तो वह हैं कमल हासन, सर। मुझे लगता है कि वह सिनेमा के लिए ही एक उपहार हैं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कई चीजों में महारत हासिल की है। उन्होंने अपना जीवन सिनेमा को दे दिया है।

नानी ने कमल हासन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई चीजों में महारत हासिल की है। इसके साथ ही कई तरह के नए-नए प्रयोग भी किए हैं। उन्होंने आगे कहा, जिस समय में उन्होंने काम किया है, उन्होंने हर चीज सबसे पहले देखी है। उन्होंने सबसे पहले डिजिटल, मेकअप ट्रायल देखा है। अब आगे से जो भी बदलाव होंगे, वो उस पैमाने पर नहीं होंगे। सिनेमा के इस पूरे विकास की प्रक्रिया में कमल सर का योगदान काफी ज्यादा है।

अभिनेता नानी शुरू में बतौर निर्देशक ही फिल्मी करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि किस चीज ने उन्हें निर्देशन को लेकर प्रेरित किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि अलग-अलग समय पर उन्हें अलग-अलग निर्देशकों ने प्रेरित किया।

इस लड़की ने 23 साल से नहीं खाया अन्न, फिर भी पूरी तरह है फिट

अलीगढ़- कहा जाता है कि अगर जन्म से कोई अलौकिक शक्ति के साथ पैदा होता है तो उसे भगवान का अवतार माना जाता है। कुछ ऐसा ही जीवन अलीगढ़ की एक लड़की जी रही है। यहां के सरसौल इलाके में रहने वाली 23 साल की कृष्ण शर्मा ने अपने अनोखे आहार और जीवनशैली से सबको हैरत में डाल दिया है। उनका दावा है कि जन्म से लेकर अब तक उन्होंने कभी अन्न ग्रहण नहीं किया, फिर भी वह पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय हैं। उनका यह जीवनशैली चिकित्सा और विज्ञान की दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। कृष्ण शर्मा की ये असाधारण कहानी न केवल उनके परिवार और पड़ोसियों के लिए चौंकाने वाली है, बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। जहां आम इंसान के लिए अन्न ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत माना जाता है, वहीं कृष्ण की जीवनशैली इस धारणा को चुनौती देती है। कृष्ण शर्मा ने बताया कि उन्होंने बचपन से ही अन्न नहीं खाया। वह केवल फल और जूस पर जीवन यापन करती हैं। उनका कहना है कि अगर वह अन्न से बना कुछ भी खाती हैं, तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक बार उनके पिता ने उन्हें रोटी खिलाने की कोशिश की थी, जिससे उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कृष्ण का मानना है कि उनके इस असाधारण आहार के पीछे भगवान का आशीर्वाद है. वह भगवान में गहरी आस्था रखती हैं और मां वैष्णो देवी की भक्त हैं. उन्होंने कहा, मुझे कभी अन्न खाने की भूख नहीं लगती और ना ही मैंने कभी अन्न खाया है. मुझे कभी कोई कमजोरी या बीमारी महसूस नहीं होती। कृष्ण शर्मा ने अलीगढ़ के विवेकानंद कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है और अब वह आईएएस की तैयारी कर रही हैं। उनका सपना है कि वह एक दिन कलेक्टर बनें। उनके परिवार में छह बहन-भाई हैं, और वह दूसरे नंबर पर हैं। उनके पिता धीरेन्द्र शर्मा ट्रांसपोर्ट का छोटा सा बिजनेस करते हैं, जबकि उनकी मां रेखा शर्मा एक हाउसवाइफ हैं। इस अनोखी स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, अलीगढ़ के डॉक्टर विकास मल्होत्रा ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने आहार में केवल फल, मेवा, जूस और नींबू पानी का इस्तेमाल करता है, तो वह बिना अन्न खाए भी जीवित रह सकता है। हालांकि, कृष्ण की स्थिति दुर्लभ और अनोखी है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक अध्ययन का विषय हो सकती है।

अजब-गजब | पूरी दुनिया से सात साल पीछे चल रहा है यह देश

धरती का इकलौता देश, यहां होते हैं साल में 13 महीने

दुनियाभर के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, जाति और धर्म हैं। लेकिन इन तमाम जगहों पर अगर कोई एक बात सामान्य है, तो वो है साल और महीने। लेकिन दुनिया में कई ऐसी भी संस्कृतियां मौजूद हैं जो साल और तारीख जानने के लिए अलग-अलग तरह के कैलेंडरों का प्रयोग करती हैं। ये सारे कैलेंडर पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसे नहीं है। पर वो सभी साल में 12 महीने ही मानते हैं। लेकिन इस धरती पर एक देश ऐसा है, जहां पर साल में 12 नहीं, बल्कि कुल 13 महीने होते हैं। आपको जानकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। इतना ही नहीं, 13 महीनों की वजह से ये देश पूरी दुनिया से 7 साल पीछे चल रहा है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो पोस्ट भी वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो पोस्ट के मुताबिक, इस अफ्रीकी देश का नाम इथियोपिया है। इथियोपिया में 1 साल में कुल 13 महीने होते हैं, जिसमें 13वें महीने में कुल 5 दिन होते हैं, जबकि सप्ताह में कुल 5 दिन। लेकिन जिस साल लीप ईयर होता है, उस साल इथियोपिया के कैलेंडर में 6 दिन होते हैं।आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बता दें कि 2024 का नया साल पूरी दुनिया मना चुकी है, लेकिन

इथियोपिया में इसे 11 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। बता दें कि दुनिया के ज्यादातर देशों में पश्चिमी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही मान्यता दी गई है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं, जो अपने प्राचीन कैलेंडर को मानते हैं। हालांकि, इसके बावजूद सभी कैलेंडरों में 12 महीने ही होते हैं, लेकिन इथियोपिया में आज भी उसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है जो रोमन चर्च ने 525 एडी में अमेंड किया था। इस वजह से इथियोपिया में नई सदी की शुरुआत 11 सितंबर 2007 से हुई थी।

बता दें कि इथियोपिया इकलौता ऐसा अफ्रीकी देश है, जो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं हुआ। इस पर कभी इटली का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 6 साल बाद ही वो भी चले गए। इतना ही नहीं, उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इथियोपिया में ही कॉफी की उत्पत्ति हुई थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक इस वीडियो पोस्ट पर अब तक 5 लाख 49 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। वहीं, हजारों लोगों ने इसे शेयर और लाइक किया है। कमेंट्स भी खूब आ रहे हैं। इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कुछ यूजर अन्य दूसरे देशों के बारे में जानना चाहते हैं। वहीं, कई यूजर्स मजे लेने के मूड में दिखे। वीडियो पर कमेंट करते हुए जितेंदर भल्ला ने लिखा है कि हमारे भारत में भी 13 महीने का साल होता है, यकीन न हो तो मोबाइल कंपनी के हिसाब से लगाकर देख लो। वहीं, अजीम नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है कि अफ्रीका का यह देश वाकई में अद्भुत है। हमें ऐसी जानकारी नहीं थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक, महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च आदि हैं, लेकिन इथोपियन यानी गीज कैलेंडर के महीनों के नाम भी अलग-अलग हैं। पहला महीना मेस्केरम है, जो नए साल का महीना है। इस महीने की शुरुआत 11 सितंबर से होती है। इसके बाद दूसरा महीना है टिकिम्त । फिर हिदार, तहसास, तिर, याकातित, मग्गाबित , मियाजिया, गिनबोत, सेंसे, हामले, नेहासा और पागुमे हैं।

फर्रुखाबाद कांड पर गरमाई सियासत, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले-

भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद एक गुनाह

» बोले- सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार

» अखिलेश और प्रियंका गांधी ने भी उठाए सरकार पर सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दो युवतियों की हत्या को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। राहुल ने कहा कि फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का ऐसा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि आखिर यह सब कब तक सहन किया जा सकता है? एक समाज के रूप में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार है और न्याय हर पीड़ित परिवार का हक है। दरअसल, 27 अगस्त को यूपी के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज इलाके में दलित समाज की 2 युवतियों के शव पेड़ से लटके मिले थे। जहां दोनों सहेलियां जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर कार्यक्रम देखने निकली थीं, मगर घर वापस नहीं पहुंचीं। जब परिजनों ने तलाश की तो उन दोनों बच्चियों के शव एक ही दुपट्टे से लटकते हुए मिले थे। वहीं, इनमें से एक युवती के पिता ने अपनी बेटी की हत्या की आशंका जताई है। फर्रुखाबाद जिले की पुलिस ने रेप और हत्या की आशंका से साफ इनकार किया है। पुलिस इस मामले को सुसाइड से जोड़कर देख रही है। इस मामले पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार में दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।

न्याय हर पीड़ित परिवार का हक

प्रियंका गांधी ने भी घटना पर उठाए सवाल

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने सवाल किया कि क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, महिलाएं, या जो भी कमजोर हैं, वे न्याय की आशा छोड़ दें।

प्रियंका गांधी ने लड़कियों के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए पोस्ट किया कि इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सुलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है?

अंतिम संस्कार का लक्ष्य सबूत मिटाना : अखिलेश यादव

वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले का एक वीडियो शेयर करते हुए मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहा है, जिसमें कहा गया था कि यह पहली नजर में आत्महत्या का मामला नजर आता है। वह व्यक्ति कहता है कि शरीर पर चोट के निशान हैं और कांटे चूभे हुए हैं। बेल के कांटे आप जानते हैं कितने बड़े होते हैं। हमें शव देखने नहीं दिया। हम कुछ भी मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो मामला है उसमें आपने ये पता लगा लिया कि इन्होंने अपने आप फांसी लगाई है। जो चोट के निशान थे तो आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। ये जांच सारी फर्जी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि आनन-फानन में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है? ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रूखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। जाहिर है कि एक ओर सरकार की तरफ से प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था का दावा किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में आये दिन हो रही आपराधिक घटनाएं व हत्याएं सरकार के ऐसे दावों की पोल खोलती हैं। यही कारण है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और प्रदेश में जंगलराज होने की बात दोहरा रहा है।

हरियाणा में दिग्गजों को टिकट नहीं देगी कांग्रेस!

» प्रदेश प्रभारी बोले- रास-लोस सांसद चुनाव लड़ने की बजाय प्रचार पर करें फोकस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से अब सभी की निगाहें उम्मीदवारों की लिस्ट पर है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया है। इसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बार टिकट मिलेगा या नहीं।

बाबरिया ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की जो दावेदारी होगी उस पर कमेटी का रुख ये है कि उन्हें चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव प्रचार पर फोकस करना चाहिए। सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा सिरसा या अंबाला की किसी विस सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं, जबकि सुरजेवाला अपनी पारंपरिक सीट कैथल से चुनावी ताल ठोकना चाहते हैं।

कुमारी शैलजा और सुरजेवाला ने चुनाव लड़ने की जताई थी इच्छा

इससे पहले कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि अब दीपक बाबरिया के बयान के बाद देखना होगा कि कांग्रेस इन सांसदों को विधानसभा चुनाव में टिकट देती है या नहीं।

शव पर राजनीति कर लाभ लेना चाहती है भाजपा: ममता बनर्जी

बोलीं- अगर बंगाल में आग लगाई तो उसका असर कई राज्यों में होगा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार की नीति बलात्कार संबंधी घटनाओं को कतई बर्दाश्त न करने की है। लेकिन इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसपर सियासी बवाल होना अब तक है। सीएम ममता बनर्जी ने रैली में कहा कि चिकित्सक बलात्कार-हत्या मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कोलकाता पुलिस से अपने हाथ में लिए हुए 16 दिन बीत चुके हैं न्याय कहां है?

उन्होंने 12 घंटे के बंद के आह्वान के लिए भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने बंद का आह्वान किया, क्योंकि वे एक शव से राजनीतिक लाभ चाहते थे। भाजपा एक युवती की मौत के मद्देनजर आम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। वे बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं और घटना की जांच को पटरी से उतारने की साजिश रच रहे हैं, ताकि पीड़िता और उसके परिवार को न्याय न मिले।

पीएम मोदी ने क्यों नहीं दिया इस्तीफा

बंगाल सीएम ने आगे कहा कि अगर बंगाल में आग लगाई गई तो इसका असर असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली में भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय ने हाल ही में राजनीतिक दलों और व्यक्तियों पर महाराष्ट्र बंद करने पर रोक लगाई थी। आरजी कर अस्पताल की घटना के मद्देनजर उनके इस्तीफे की मांग पर बनर्जी ने कहा कि मैं भाजपा से पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर और असम में महिलाओं पर अत्याचार और यौन हमलों को रोकने में अपनी विफलता के लिए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। मैं पूछती हूं कि असम में मुठभेड़ में केवल एक आरोपी ही क्यों मारा गया? बनर्जी ने कहा कि भाजपा ऐसी मांग इसलिए कर रही है क्योंकि उसे चुनावों में लगातार हार का सामना करना पड़ा है और वह जानती है कि वह भविष्य में भी जीत नहीं पाएगी। एआई का उपयोग कर बड़े पैमाने पर साइबर अपराध कर रही है जिससे सामाजिक अशांति पैदा हो रही है।

पेरिस पैरालंपिक का हुआ शानदार आगाज

» सुमित और भाग्यश्री बने ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक

» 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगे खेल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पेरिस। ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस के बीचों-बीच एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ हो गई है। ओपनिंग सेरेमनी प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैंप्स-एलिसीस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर हुई।

इस बार पैरालंपिक गेम्स 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस में होने हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी के लिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। दोनों ने तिरंगे को लहराते हुए एंट्री की और उनके साथ पूरा भारतीय दल भी रहा। पेरिस पैरालंपिक 11 दिनों तक चलेंगे। अमूमन पैरालंपिक आमतौर पर स्टेडियम के अंदर होते हैं, लेकिन पारंपरिक समारोहों के विपरीत, इस बार पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह खुले में हुआ। जिसमें शहर के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्थल शामिल रहे, जिनमें एफिल टॉवर, प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और ट्रोकाडेरो हैं। पेरिस पैरालंपिक की शुरुआत प्रतिष्ठित चैंप्स-एलिसीज पर भव्य परेड से हुई, जिसमें दुनिया भर से 184 देशों का प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। ओपनिंग सेरेमनी में 6,000 एथलीट और अधिकारी शामिल हुए।

भारत की ओर से 84 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

भारत की ओर से पेरिस पैरालंपिक में 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया है। सभी एथलीट 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। 2021 में हुए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में हिस्सा लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 24वां स्थान हासिल किया था। यह उसका इन गेम्स में बेस्ट प्रदर्शन था। इस बार भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस में 25 पदक जीतने का लक्ष्य रखा है।

रेप की घटनाओं पर बसपा प्रमुख की केंद्र व राज्य सरकारों से अपील

राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए सरकार : मायावती

» बोलीं- इन मामलों पर न की जाए राजनीति, यही महिलाओं के हित में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बीते दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में दिल दहला देने वाली बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। आए दिन सामने आ रहीं ऐसी घटनाओं पर सरकारें एक्शन तो ले रही हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।

वहीं दूसरी ओर इन राज्यों में हुई रेप की घटनाओं पर जमकर सियासत भी लगातार की जा रही है। अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बलात्कार की इन घटनाओं पर चिंता जताई है और सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा व फर्रूखाबाद जिले आदि में भी मासूम बच्चियों, नाबालिग व महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या व आत्महत्या आदि की हो रही घटनाएं अति-दुःखद व चिन्ताजनक हैं। बीएसपी चीफ ने आगे कहा कि केंद्र व सभी राज्य सरकारें, इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं, ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी होना बन्द हों। ना कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए, यही समय की मांग है तथा यही महिलाओं के हित में भी है।

बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना पर जारी है बवाल

बीते कुछ दिनों के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में रेप की घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ रेप और फिर हत्या की घटना पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन घटनाओं के बीच अब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भी रेप की घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दो युवतियों का शव आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिलने के बाद तमाम सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसमें पुलिस ने कहा है कि यह मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ लगता है।

बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा झटका

» अदालत ने रद्द की पूर्व बीजेपी सांसद की याचिका

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण के वकील से मामले में एक शार्ट नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृजभूषण से कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए। यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

एफआईआर कराने के पीछे एक हिडेन एजेंडा: बृजभूषण

बृजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में छह शिकायतकर्ता हैं, एफआईआर दर्ज कराने के पीछे एक हिडेन एजेंडा है। वकील ने कहा कि सभी घटनाएं अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर हुई हैं। यह सिर्फ एक साजिश के तहत किया गया काम है। हालांकि, कोर्ट में वकील की दलीलें काम नहीं आई और उनके खिलाफ सुनवाई जारी रहेगी।

फोटो: 4 पीएम

कार्यशाला भाजपा प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यशाला का दीप जलाकर शुभारंभ करते प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व धर्मपाल सिंह।

अगले पांच दिनों तक नहीं बनेंगे पासपोर्ट

नहीं होगा कोई नया अपॉइंटमेंट, पहले से बुक वाले भी होंगे रिशेड्यूल

» ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल पर नहीं होगा कोई काम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ऑनलाइन पासपोर्ट पोर्टल पर अगले पांच दिनों तक कोई काम नहीं होगा। इस दौरान जारी किए गए सभी अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किए जाएंगे।

सरकार ने कहा कि पासपोर्ट आवेदनों के लिए ऑनलाइन पोर्टल रखरखाव प्रकिया की वजह से अगले पांच दिनों के लिए बंद रहेगा। इस दौरान कोई नया अपॉइंटमेंट शेड्यूल नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही पहले से बुक किया गया अपॉइंटमेंट फिर से शेड्यूल किया जाएगा।

पासपोर्ट सेवा पोर्टल ने जारी किया एक नोट

पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर भी एक नोट जारी किया गया है। जारी किए गए इस नोट में कहा गया कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल 29 अगस्त 2024, गुरुवार रात आठ बजे से 2 सितंबर, सोमवार सुबह छह बजे तक तकनीकी रखरखाव के लिए बंद रहेगा। इस दौरान नागरिकों और सभी MEA/ RPO/ BOI/ ISP/DoP/पुलिस अधिकारियों के लिए सिस्टम उपलब्ध नहीं रहेगा। 30 अगस्त 2024 के लिए पहले से बुक किए गए अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल किया जाएगा। इसकी सूचना आवेदकों को समय से पहले ही दे दी जाएगी।

यह एक नियमित प्रक्रिया : विदेश मंत्रालय

मामले में विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह एक आम और नियमित प्रक्रिया है। अपॉइंटमेंट को फिर से शेड्यूल करने के लिए हमारे पास हमेशा औचक योजना होती है। सार्वजनिक केन्द्रित सेवा (जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र) के लिए रखरखाव की योजना हमेशा पहले से बनाई जाती है, ताकि जनता को परेशानी न हो। इसलिए अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं आएगी।

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ जारी, तीन आतंकी ढेर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है और अगले महीने से चुनावी समर शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। इस बीच एक बार फिर आतंकियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, कुपवाड़ा में दो अलग-अलग मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षाबलों ने माछिल में दो और तंगधार में एक आतंकी के मार गिराया है। कुपवाड़ा में अभी मुठभेड़ जारी है। वहीं, राजौरी में भी सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि इलाके में दो से तीन आतंकी छिपे होने की आशंका है। मुठभेड़ खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल इलाके में बुधवार देर रात शुरू हुई। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है।

एलओसी से घुसपैठ का था इनपुट

ऐसा इनपुट था कि आतंकियों का ग्रुप एलओसी से तंगधार सेक्टर में घुसपैठ कर सकता है। इस सूचना पर एलओसी पर सतर्क सेना के जवानों ने मोर्चा लगाया था। देर रात खुशहाल पोस्ट के पास संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद जवानों ने ललकारा तो दूसरी ओर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। जवानों की ओर से पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी गई है ताकि अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकी घुसपैठ करने में सफल न हो जाएं।

बुधवार रात से शुरू हुआ अभियान

जम्मू-कश्मीर पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त को रात 9.30 बजे सुरक्षाबलों ने राजौरी के खेड़ी मोहरा लाठी और दंथल क्षेत्र के इलाकों में एक तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान लभग 11.45 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हुआ। जिसके बाद खेड़ी मोहरा इलाके के पास आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। उधर, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में बुधवार देर रात घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया।?विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश के तहत सीमा पार से आतंकियों को धकेलने की कोशिश की गई थी। पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है।

स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक **संजय शर्मा** द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित एवं 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। **संपादक** - संजय शर्मा, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website:** www.4pm.co.in |
RNI-UPHIN/2015/62233 डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।